VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	RAKESH KUMAR MEENA		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	19016
Center	ONLINE	Date	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. "Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

Scanned with CamScanner

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद → संविधान + (वाद)

संविधान ↓ देश का सर्वोच्च कानून

वाद ↓ विचारधारा

देश की स्वतंत्रता वाले विचारों को लेकर बनाया गया सर्वोच्च विधान → संविधानवाद

भारतीय संविधान में विभिन्न उपबंध –

① प्रस्तावना :- समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय तथा समाजवाद व पंथनिरपेक्षता (42nd CAA) जैसे मूल्य

② मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व
(अनुच्छेद 12-35) (अनुच्छेद 37 - 51)

③ संविधान का 'जीवंत दस्तावेज' के रूप में न्यायपालिका द्वारा संरक्षण — न्यायिक पुनर्विलोकन (मिनर्वा मिल्स) तथा संविधान का आधारभूत ढांचा (केशवानंद भारती)

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

④ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार (अनु. 326)

⑤ संघवाद की विशेषताएँ - ~~सामान्य~~ सूचियों के अनुसार क्षेत्र विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कठोर संविधान संशोधन (अनु 368)

⑥ सिविल सेवाओं के माध्यम से नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन को लागू कर कल्याणकारी राज्य बनना (अनु 312 - 321)

संविधानवाद वर्तमान समय में बढ़ता राजनीतिक अपराधीकरण, धार्मिक कट्टरपंथ (उदयपुर घटना) के कारण खतरे में अक्सर नजर आता है लेकिन शासन के तीनों अंगों संतुलन इसको जीवित रखने में मदद करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग → 2002 में कानून, objective → कंपनियों के लिए बेहतर वातावरण, उपभोक्ताओं के लिए सही कीमत निर्धारण, व्यापार कुशलता को बढ़ावा देना।

CCI द्वारा किए गए प्रमुख कार्य

1. अवैध सीमेंट कार्टेलाइजेशन को रोकना तथा सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना
2. प्रिडेटरी प्राइसिंग से बचने के लिए JIO जैसी बड़ी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

उपरोक्त उदाहरण उपभोक्ता कल्याण में CCI की भूमिका को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट करता है लेकिन CCI कुछ चुनौतियों से जूझ रही है-

① CCI के पास तकनीकी मानव संसाधन तथा अवसंरचना की कमी

② विभिन्न नियामकीय संस्थाओं के कारण क्षेत्रों की overlapping जैसे उपभोक्ता संरक्षण आयोग तथा CCI के मध्य क्षेत्र अधिव्यापकता

③ CCI की रिपोर्ट का अनुपालन केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं

④ वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव तथा MNC कंपनियों का सेनाधिकार व्यापक होना।

CCI को बेहतर कार्मिक और अवसंरचना प्रदान कर एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.
(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

COVID-19 के दौर में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी मामलों के निस्तारण में मददगार रही।

न्यायालयों में लंबित मामले (National Judicial Data Grid) → लगभग 4 cr जिनमें से 60000 मामले SC में लंबित

ऑनलाइन प्रदायगी की विभिन्न पहलें :-

① youtube पर न्यायिक कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण (अहमदाबाद HC की अनूठी पहल)

② e-court के माध्यम से Digital governance को बढ़ावा (Delhi HC)

③ Pro bono योजना - अधिवक्ताओं की online registry का निर्माण

④ CCTNS तथा NATGRID के माध्यम से आपराधिक न्यायिक प्रणाली को मजबूती

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :-

① Cyber सुरक्षा - ITU के cyber security Index में भारत की खराब स्थिति

② अवसंरचना की कमी, HC तथा निचले न्यायालयों में उपलब्ध ना होना

③ Digital literacy की कमी - WB के अनुसार भारत की 80% जनता इंटरनेट का प्रयोग करना नहीं जानती

④ Digital privacy का खतरा न्यायिक कार्यवाहियों को हैक कर न्यायिक सेवा में बाधा पहुँचाना

लेकिन चुनौतियों को Digital India, PM GDISHA, तथा क्वाड्स India (भारतनेट) का बेहतर क्रियान्वयन कर पार पाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. (150 words) 10

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संवैधानिक मूलाधिकारों का वास्तविक उद्देश्य जनता को सर्वोपरि बनाना तथा राज्यों के कार्यों में यथोचित प्रतिबंध लगाना।

भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 12-35 तक है जो नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं।

वहीं USA के संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से USA के नागरिकों के अधिकारों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

भारत	USA
① अधिकारों का व्यापक वर्णन	① अधिकारों का सीमित वर्णन
② अधिकारों के प्रवर्तन में SC/HC के पास	② अधिकारों का प्रवर्तन केवल SC के पास

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(3) अधिकारों के तहत राज्य की शक्ति पर सकारात्मक प्रतिबंध	(3) अधिकारों पर राज्य की शक्ति पर नकारात्मक प्रतिबंध
(4) अधिकारों के प्रवर्तन के लिए writs का प्रावधान	(4) writs का प्रावधान नहीं
(5) सेनाओं तथा पुलिस बलों के अधिकारों का वर्णन	(5) ऐसा वर्णन आयरिश संविधान में नहीं
(6) राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12)	(6) राज्य को परिभाषित नहीं करता है।

दोनों ही देशों में मूल अधिकारों को शामिल करना नागरिकों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बहाली का सशक्त माध्यम है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें।)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना, स्थानीय आदिवासियों को उनका अधिकार तथा ग्राम सभा को मजबूत बनाना।

FRA 2006 के धीमे क्रियान्वयन के कारण :—

1. ग्रामसभा को संसाधन तथा कौशल प्रशिक्षण का अभाव
2. forest Bureaucracy के साथ झगड़ा
3. विकास के नाम बिना EIA (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन) के प्रोजेक्ट चलाना
4. कानूनों के क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी
5. जागरूकता संबंधी अभियानों पर कम खर्च
6. CAMPA के माध्यम से FRA की मूल चिंता को हटाने की कोशिश

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

FRA के बेहतर क्रियान्वयन के
लिए → Way forward

(1) ग्रामसभा को बेहतर कौशल तथा संसाधन उपलब्ध करवाएँ।

(2) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संशोधनों भागीदारी प्रभाव मूल्यांकन बनाने की आवश्यकता

(3) समन्वय:- Forest Bureaucracy के साथ बेहतर तालमेल की कोशिश।

(4) GST परिषद की तर्ज पर Forest Council का निर्माण - ताकि बेहतर ढंग से निर्णय

(5) टारगेटेड मोड पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता

आदिवासी अधिकार तथा विकासात्मक भारत की बुनियादी सोच में संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

Social stock exchange – सामाजिक समस्याओं के बेहतर तरीके (stock के माध्यम से फंड इकट्ठा करना) समाधान की कोशिश करने के लिए महत्वपूर्ण पहल

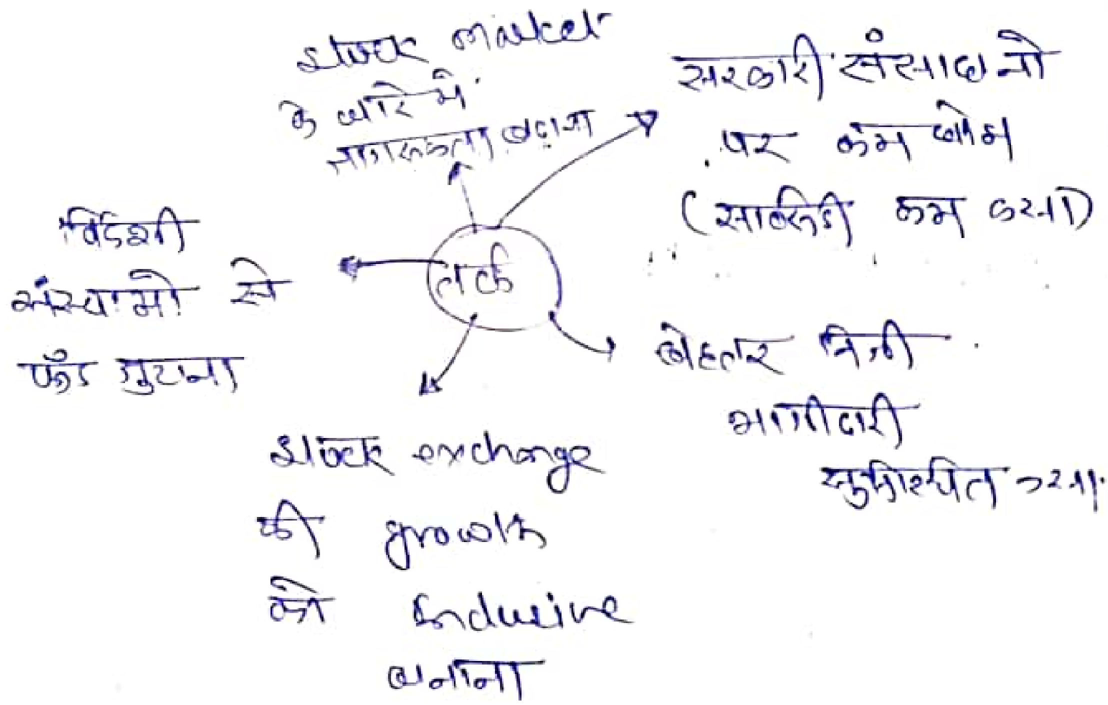

सामाजिक प्रभाव :-

सकारात्मक :- ① संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए फंड की उपलब्धता

② शिक्षा (3% of GDP) और स्वास्थ्य (1.8% of GDP) क्षेत्र में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ सब्सिडी कम होने से राजकोषीय समेकन पर सकारात्मक प्रभाव

नकारात्मक: ① अभी निश्चित नहीं कि किन सामाजिक कार्यों में करें

② Stock exchange की जटिलताओं के बारे में आम नागरिक को जानकारी नहीं

③ सरकारी नियम तथा विनियमन Social stock exchange. को लेकर स्पष्ट नहीं

Social Stock exchange भविष्य में सामाजिक प्रभाव तथा भारत के SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

Scanned with CamScanner

anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 60% out of pocket cost,
1.5% of GDP (NHP 2017 - 2.5% of GDP)
तथा बढ़ते Pandemic - COVID-19 आदि
राष्ट्रीय Digital Health
Mission (NDHM) के objective

- सभी नागरिकों को Health ID
- सभी डॉक्टरों की Public Registry तैयार करना।
- Tele medicine को बढ़ावा देना
- सभी मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी डाटाओं को संरक्षण के लिए Health Registry

क्रांति का वाहक :-

- Co-morbidity को कम - COVID में ऐसे मरीजों की पहचान नहीं होने से मृत्यु
- डॉक्टर मरीज अनुपात को बेहतर

anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

अभी (10/10 भारत की संकल्पना पर)

- डिजिटल प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषज्ञों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाना।
- मरीजों की Registry उनके बेहतर उपचार में मदद करेगी।

चिंताएं:- (1) साइबर सुरक्षा खतरा
(2) मरीजों की निजी सूचनाओं का संरक्षण (अभी कोई Data Protection कानून नहीं)
(3) डिजिटल निरक्षरता तथा डिजिटल अवसंरचना की कमी
(4) आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी

हालांकि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तथा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर करने का प्रयास कर रही है तथा Blockchain प्रौद्योगिकी, Quantum Mechanism बेहतर Data Protection में सहायक हो सकते हैं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. (150 words) 10

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

उच्चतर शिक्षा में Gross enrolment Ratio 14% के स्तर पर बना हुआ है तथा सर्वशिक्षा अभियान के पश्चात Dropout Rate काफी अधिक है

निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनिवार्यता

(1) शिक्षा के क्षेत्र में GDP का केवल 3% व्यय (NEP 2020 - 6% of GDP)

(2) सकल नामांकन अनुपात कम (NEP 2020 - 25% तक बढ़ाना)

(3) सरकारी शिक्षकों की कमी और जहाँ है वहाँ उनकी उचित Teaching capacity का अभाव

(4) India Skill Report - केवल 47% Graduate ही रोजगार की क्षमता से परिपूर्ण।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निजी क्षेत्र की भागीदारी से मुद्दे

① शिक्षा का व्यावसायीकरण।

② शिक्षा की गरीब वर्गों तक पहुंच मुश्किल

③ केवल शहरी तथा sub-urban केन्द्रों तक निजी शिक्षा सीमित।

हालांकि इनका समाधान बेहतर

नियमन से किया जा सकता है -

① निजी क्षेत्र का बेहतर विनियमन करने के लिए राज्यीय/क्षेत्रीय आयोगों का गठन

② Capitation fee को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है (सभी हितधारकों को शामिल करके)

③ HEFA का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

④ Industry - Academia का मेलजोल कर बेहतर vocation training Provide करसके

⑤ Digital technology और MOOC DISHA आदि का प्रयोग करें।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें।)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. **(150 words) 10**

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

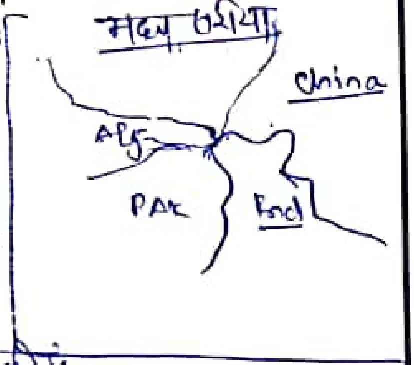

भारत की Connect Central Asia रणनीति

मध्य एशिया का भारत के लिए महत्व दर्शाते हुए

① geo political तथा geo economic महत्व

मध्य एशिया का क्षेत्र, सैन्याधान संपर्क तथा यूरोपीय देशों तथा अफगानिस्तान से जुड़ाव

② महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा: TAPI gas pipeline तथा ONGC -विदेश limited द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश।

③ निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के लिए निवेश की संभावना के द्वार खोलना

④ सांस्कृतिक जुड़ाव.. भारतीय संस्कृति का मध्य एशिया में ख्याति है (India cinema

⑤ डायस्पोरा तथा उनसे प्राप्त Remittance

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ :-

① प्रत्यक्ष भौगोलिक जुड़ाव नहीं - PoK का पाकिस्तानी नियंत्रण

② चीन का BRI Project साथ ही भौगोलिक जुड़ाव

③ Afganistan पर तालिबान का कब्जा प्रभाव - TAPI gas pipeline Project को प्रभावित कर सकता है

④ Oil price की कीमतों में उतार-चढ़ाव

⑤ ISIS तथा भारत में बिगड़ता धार्मिक सद्भावना का माहौल

हालाँकि इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने मध्य एशिया में INSTC जैसी प्रमुख पहलों से जुड़ाव स्थापित किया है।

anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. (150 words) 10

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत का लगभग 18 million Diaspora विश्व में फैला हुआ है जो कि सर्वाधिक है तथा Remittence के रूप में लगभग $60 bn वार्षिक प्राप्त होता है। भारत एक 'वैश्विक निर्भर नागरिक' की भूमिका में नजर आता है।

Diaspora की आत्मनिर्भर भारत में भूमिका

1. भारतीय प्रवासियों द्वारा विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार-प्रसार करना (निर्यात में बढ़ोतरी)
2. विदेशों से तकनीकि कौशल तथा पूंजी का निवेश भारतीय क्षेत्रों में करना
3. भारतीय विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका (अमेरिका से सिविल नागरिक परमाणु समझौता)

anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(4) Track-II diplomacy के माध्यम से Business to Business तथा People to people contact को बढ़ावा।

चुनौतियाँ

(1) Brain Drain की समस्या
(2) संरक्षणवाद का बढ़ता प्रभाव
(3) वैश्वीकरण कम होने के कारण विकसित देशों में बेरोजगारी संकट (नीतियों में परिवर्तन)
(4) वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में भारत की कम भागीदारी।

Way forward

(1) भारत को अपनी प्रवासी भारत कौशल योजना का क्रियान्वयन
(2) 'मजबूरन प्रवासी' से 'रणनीतिक प्रवासी' बनाने पर ध्यान केंद्रित
(3) प्रवासी भारतीयों की वैश्विक मिशन जैसी पहलों से प्रवासियों का विकास किया।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74 वाँ संविधान संशोधन 1994 — स्थानीय निकायों का विकास कर grass-root level democracy को बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रमुख लक्ष्य

सकारात्मक परिणाम

1. अनुच्छेद 243 D के माध्यम से SC/ST/महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी
2. स्थानीय निकाय जिला आयोजना समिति तथा महानगरीय आयोजना समिति के माध्यम से मास्टर प्लान का निर्माण
3. 14वें/15वें वित्त आयोग द्वारा फंड सीधे स्थानीय निकायों को देने की अनुशंसा

नकारात्मक परिणाम

1. सरपंच पति/प्रधान पति प्रवृत्तियां
2. fund, function, functionary, functionality की कमी (2nd ARC)
3. स्थानीय कार्यों में कार्यों की अति व्यापकता (दिल्ली के निकायों में गलत कार्य आदि का शहरी निकायों से संगठित समन्वयता)

स्थानीय निकायों में ड्रग्गी-पीपी के सुधारों की आवश्यकता है—

① शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को 30 वर्षीय मास्टर प्लान बनाने का कार्य → इसके लिए विषय विशेषज्ञों की टीम स्थानीय हितधारकों को सम्मिलित कर बनाएं

② ULB's में फंड की आवश्यकता के लिए परिणाम आधारित ULB, में Municipality Bond (अहमदाबाद) जारी किया जाए।

③ ULB's को Digital अवसंरचना तथा स्थानीय कर के लिए SWAMITVA जैसी अवधारणा शहरी क्षेत्रों में लागू की जाए

④ ULB's में खातों तथा उनके नियंत्रण सहीयता के लिए कार्मिकों की भर्ती की जाए

⑤ प्रधान / नगरपरिषद सभापति तथा मेयरों को आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ङ) Right to Recall को लागू करना

(च) राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन आयोग की स्थापना की जाए ताकि ULB's पर नियंत्रण रखा जा सके (विधि आयोग)

74 वाँ संविधान संशोधन

गांधीजी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर आधारित है ताकि बेहतर तरीके से Bottom-up Approach को लागू किया जा सके।

Scanned with CamScanner

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. (250 words) 15

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

IR Coheło case में सुप्रीम कोर्ट ने नौवी अनुसूची में शामिल मामलो (24 अप्रैल 1974) का भी न्यायिक पुनर्विलोकन का निर्णय लिया है।

नौवी अनुसूची में शामिल कानूनों का इस मामले से पहले Judicial Review की परिधि से बाहर होता था। नो कि संसदीय आधिपत्य को प्रदर्शित करता है।

शुरुआत में जमींदारी कानूनों के उन्मूलन तथा भूमि सुधार संबंधी कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए इस सूची का प्रयोग किया था ताकि संपत्ति के मूल अधिकार से उलझा किसी

लेकिन धीरे-धीरे इसका प्रयोग 'राजनीतिक कुलीकरण' तथा 'क्षेत्रीय आकांक्षाओं' की पूर्ति के लिए (तमिलनाडु का 69% आरक्षण बिल) किया जाने लगा। (वर्तमान में लगभग 284 कानून 9 वी अनुसूची में शामिल)

संविधान की सर्वोच्चता 9 वी अनुसूची के कारण कम होने लगी। क्योंकि संविधान 'ज्यूडिशियल रिव्यू' के रूप में स्वयं को न्यायालयों के निर्णयों से सुरक्षित रखता है।

9 वी अनुसूची judicial review को नकार कर शासन के तीनो अंगों में संतुलन बिगाड़ करती है।

लेकिन IR Coelho Case में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9वीं अनुसूची का महत्व स्थिति महत्वपूर्ण कानून जो संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है, के लिए प्रासंगिक हो गया है।

Scanned with CamScanner

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

असममिति – राज्यों के मध्य तथा केन्द्र - राज्य के मध्य शक्ति विभाजन

असममिति लोकतंत्र में विभिन्न मांगो को जन्म देती है –

(1) संसाधनों का असमानपूर्ण वितरण

(2) राज्यों को जो पिछड़े हुए है उनके लिए अतिरिक्त पूंजी तथा अवसंरचना की आवश्यकता (विशेष पिछड़े राज्यों का दर्जा)

(3) केन्द्र और राज्यों के मध्य समवर्ती सूची को लेकर टकराव से समायोजित करने की मांग

(4) वित्त आयोगो द्वारा क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान न देने वाली अनुशंसा

Scanned with CamScanner

संविधान में विभिन्न असमानताओं का संतुलन के लिए बेहतर प्रावधान

① अनुच्छेद 370 के माध्यम से पहले कश्मीर को विशेष दर्जा (अब 371)

② अनुच्छेद 371 में अधिकांशतः पहाड़ियों तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान

③ अनुच्छेद 247 में केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन

④ अनुच्छेद 275 के तहत विशेष अनुदान की व्यवस्था।

केन्द्र सरकार राज्यों को संघवाद की मूल भावना से परिचित

Scanned with CamScanner

2212

VISION IAS™

करने के लिए योजना आयोग के नीति आयोग का गठन, अंतर्राज्य परिषद में सुधार कर 'GST Council' का गठन आदि ऐसे अपेक्षित सुधार हैं जो 'सहयोगात्मक संघवाद' को बढ़ावा देते हैं।

Scanned with CamScanner

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

वित्त आयोग का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 280 तथा अनुच्छेद 243-I (पंचायतों के लिए) के तहत किया जाता है।

राज्यपाल द्वारा अपेक्षित अध्ययन

राज्य वित्त आयोग के कार्य

राज्य द्वारा प्राप्त निवल कर का स्थानीय निकायों में वितरण सुनिश्चित करना

राज्य संचित निधि के बेहतर प्रबंधन बनाने के लिए उचित उपाय करना

स्थानीय निकायों की कर अधिरोपण क्षमता में वृद्धि करना

राजकोषीय संघवाद में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका –

(1) वित्त आयोग की अनुशंसा वाले अनुदान को स्थानीय निकायों में क्षमता के साथ होना सुनिश्चित करना

anything ... margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) स्थानीय निकायों की कर उगाहने की क्षमता में वृद्धि की अनुशंसा करना।

(3) केन्द्र से प्राप्त राज्य अंतरणों का बेहतर अनुपालन तथा निगरानी सुनिश्चित करना।

(4) FRBM कानून की राजकोषीय समेकन प्रावधान को लागू करने में राज्य सरकार की सहायता करना।

किंतु राज्य वित्त आयोगों की अपनी चुनौतियाँ विद्यमान है -

(1) विभिन्न राज्यों द्वारा वित्त आयोगों का समय पर गठन नहीं किया जाना

(2) वित्त आयोगों के पास पर्याप्त मानव तथा तकनीकी संसाधनों का न होना।

(3) वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू करना राज्य सरकारों पर बाध्यकारी न होना

Scanned with CamScanner

(4) GST पश्चात राज्य की कर लगाने की शक्ति कम होगा

(5) राज्य वित्त आयोगों का राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भर होगा।

Way forward

(1) राज्य वित्त आयोगों का गठन निश्चित समयांतर में होगा (विधि आयोग)

(2) राज्य वित्त आयोग (SFC) के लिए सचिवालय तथा मानव व तकनीकी अभिलाषों की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

• वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय प्रबंधन तथा राजकोषीय संघवाद के बीच की धुरी है।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें।)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.
(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

नौकरशाही व्यवस्था (अनुच्छेद 312-322) — नीति निर्माण में भागीदारी तथा क्रियान्वयन, संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, कानून की सर्वोच्चता का अनुपालन सुनिश्चित करना

नौकरशाही के आकार में कमी का कारण :—

1. Minimum Government and Maximum Governance → प्रधानमंत्री जी के वाक्य के पालन करना
2. Lateral entry को बढ़ाना (2nd ARC) रघुराम राजन जैसे विषय विशेषज्ञों की सहायता
3. वैश्वीकरण में निजीकरण के दौर में facilitator के रूप में काम करना

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ न लिखें)

(4) कम आकार सरकारी संसाधनो पर दबाबों को कम करेगा (सेलेरी पेंशन आदि कम)

(5) होता समिति, विधि आयोग, वैकैय्यानायुडु समिति द्वारा अनुशंसित।

लेकिन नौकरशाही का आकार कम करना वर्तमान परिदृश्य मे अपेक्षित नहीं है। क्योंकि

(1) भारत मे नौकरशाही के ~40% पद रिक्त चल रहे हैं। (UN के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपेक्षित नौकरशाह के नियम का अनुपालन नहीं')

(2) जनसंख्या के बढ़ते आकार को सही तरीके से प्रबंधित करना

(3) नौकरशाही का नीति निर्माण मे योगदान।

Way forward

(1) परिणाम आधारित Promotion

(2) मिशन कर्मयोगी जैसी पहलों से नौकरशाही व्यवस्था की क्षमताओं को बढ़ावा देना

(3) पुराने तथा वर्तमान परिदृश्य के अनुकूल नहीं रहे कानूनों को समाप्त कर विवेकाधिकार कम करना (विधि आयोग)

(4) पुलिस सुधार के लिए प्रकाश सिंह मामले की अनुशंसा को लागू करना

(5) मलीमथ समिति द्वारा अनुशंसित आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार

(6) होता समिति तथा सैंथानम समिति की सिफारिशों को लागू करना

नौकरशाही भारत का 'steel framework' है जिसका भारतीय शासन में अपेक्षित सुधार समयानुकूल आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

सबरीमाला विवाद - मंदिरों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को प्रकाश में लाता है।

भारत में मूल अधिकारों के तहत धार्मिक स्थलों, ट्रस्टों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है।

लेकिन 'Doctrine of essentiality' का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्थाएं जो धार्मिक आचरण में आवश्यक नहीं है उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है।

सरकारें धार्मिक स्थानों में उचित प्रबंधन के लिए उचित प्रावधान की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है।

Scanned with CamScanner

मंदिरों का नियंत्रण क्यों आवश्यक?

① समाज के लोगों तथा व्यवस्था पर यदि मंदिर के क्रियाकलाप व्यवधान डालते हैं तो राज्य सरकार युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। (eg: UP में मस्जिद में अज़ान तथा मंदिर में हनुमान चालीसा स्पीकर से करने पर प्रतिबंध)

② मंदिर की अतिक्रमित भूमि को समाज के हित के लिए उपयोग में लाना।

③ मंदिरों में दान के रूप में प्राप्त धन पर उचित कर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

④ मंदिरों के स्थापना के लिए बने ट्रस्टों की उचित Auditing व्यवस्था सुनिश्चित करना।

Scanned with CamScanner

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्धावस्था का नारीकरण :- वृद्धावस्था की स्थिति मे महिलाओं की संख्या अधिक (~60%) तथा महिलाओं की वृद्धावस्था की स्थिति मे अत्यधिक संवेदनशील होना।

वृद्धावस्था मे महिलाओं से संबंधित समस्याएँ

① शहरीकरण से बढ़ता Nuclear family का प्रसार → वृद्ध महिलाओं की स्थिति, भावनात्मक रूप से कमजोर

② स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक खर्चीला होना तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का न होना।

③ वृद्धावस्था आश्रमों की व्यवस्था बेहद खराब, अवसंरचना संबंधी समस्या

Scanned with CamScanner

anything margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) सरकारी से प्राप्त लाभों के बारे में जागरूकता कम होना (महिला साक्षरता दर ~ 66%)

(5) कानूनी प्रक्रियाओं में देरी होने से Maintenance of old parent Act का पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं

(6) प्रशासन का महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील न होना

(7) राजनीति में महिला भागीदारी की कमी (17वीं LS में केवल 14% महिला सांसद)

(8) समाज की पितृसत्तात्मक विचारधारा महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा।

सरकार द्वारा किया गया प्रयास

(1) कानूनी व्यवस्था :- वृद्धावस्था तथा परिवार प्रावधान कानून

- Hindu succession Act

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) योजनागत लाभ :-

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
(core of the core योजना में शामिल)

- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

- राज्य सरकारों द्वारा भी विविध पेंशन संबंधी योजना।

बल्कि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार माता-पिता की देखभाल में सहायता प्रदान कर बेटियों को भी जिम्मेदारी निर्वहन का अवसर प्रदान किया।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Do not write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

सामाजिक सुरक्षा – देश के नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र या कार्य की स्थिति में न रहने की स्थिति प्रदान सहायता (DPSP – Art 43)

सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत केवल औपचारिक कार्यबल संविधिक आधार पर आता है लेकिन ~80% अनौपचारिक कार्यबल अभी भी इन सुविधाओं से वंचित है।

सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

① व्यक्तिगत लचीलापन

– दीर्घावधि जीवन की सुरक्षा की भावना

– बचत प्रवृत्ति में वृद्धि

– वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल

Scanned with CamScanner

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

खर्चों पर बेहतर तरीके से खर्च करना।

(4) व्यक्तिगत दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को मानसिक और आर्थिक संबल

(5) बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुनिश्चित

(B) <u>अर्थव्यवस्था लचीलापन</u>

- सरकारी सामाजिक योजनाओं में कमी से राजकोषीय समेकन

- 'Saving culture' में वृद्धि से निवेश के लिए अधिक पूंजी की उपलब्धता।

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज की व्यापकता में वृद्धि (IMF के अनुसार 10% social security में वृद्धि ~0.3% ↑ in GDP)

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक कार्यबल का 'औपचारीकरण' करने में सहायता

वर्तमान समय में आवश्यकता है कि श्रमिकों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आदि में भागीदारी सुनिश्चित करें।

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक संहिता कोड के माध्यम अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल तथा Gig economy को भी Social security देने का सराहनीय प्रयास किया है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss. (250 words) 15

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

वर्तमान विदेश नीति में विभिन्न देश द्विपक्षीय तथा मुद्दे आधारित गठबंधन (जैसे QUAD, SCO, BRICS, RCEP आदि) की ओर अग्रसर है।

पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था की चुनौतियां का प्रबंधन में विफलता के कारण :—

① WTO का वैश्वीकरण के दौर में संरक्षणवाद तथा नए व्यापारिक प्रतिबंधों को रोकने मे विफलता (Food Security को लेकर विकासशील देशों के मुद्दे)

② UNCLOS द्वारा चीन पर आरोपित प्रतिबंधों का चीन द्वारा न मानना

Scanned with CamScanner

③ WHO का COVID-19 जैसी महामारी के दौरान बेहतर ढंग से नियोजन करने में विफलता

④ UNFCCC के तहत आयोजित COP में अभी देशों की ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लक्षित टारगेट का प्राप्त न होना।

⑤ WB तथा IMF का भी निर्धारित शर्तों के साथ विकासित देशों की मानसिकता थोपना

⑥ UNSC में रिफार्म की आवश्यकता (Afganistan संकट, रूस-युक्रेन विवाद में असफल)

<u>वर्तमान में मुद्दे आधारित गठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता</u>

① समान विचारधारा वाली देशों के संगठन QUAD, BRICS, SAARC

Scanned with CamScanner

(2) जलवायु परिवर्तन से संबंधित — अंतर्द्वीप स्तौर ऊर्जा संगठन

(3) प्रौद्योगिकी देशों से संबंधित D-10 समूह का विचार

(4) भूराजनीतिक तथा भू-आर्थिक प्रभावों पर आधारित
RCEP, TPP+, ASEAN आदि

मुद्दे आधारित गठबंधन आर्थिक तौर पर प्रभावी हो सकते हैं लेकिन इनका प्रभाव तब अधिक होगा जब ये गठबंधन बहुपक्षीय संगठनों में सुधार लाएँगे ताकि 'Global Common' मुद्दों को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सके।

Scanned with CamScanner

Do not write anything in margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80% आयात करता है उसमें से भी ~ 85% पश्चिमी एशिया से।

भारत को अपनी energy basket में विविधता लाने की आवश्यकता है इसके लिए दक्षिण एशियाई देशों में स्थित ऊर्जा संभावनाओं का दोहन करना पड़ेगा -

① भारत, नेपाल के साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौता कर Hydro power plant की संभावना को बढ़ा सकता है।

② बांग्लादेश के साथ संचालित रूपपुर परमाणु बिजलीघर परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

Scanned with CamScanner

(3) मालदीव तथा मलेशिया जैसे देशों से OTEC तथा wave energy की संपदा का दोहन कर सकता है।

(4) अफगानिस्तान में तथा मध्य एशिया में स्थित प्राकृतिक गैस का ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति मे उपयोग

लेकिन दक्षिण-एशिया मे ऊर्जा आवश्यकताओं में एक gap नजर आता है - प्रमुख कारण -

(1) भारत के अलावा दक्षिण-एशिया में स्थित देशों का वित्तीय तथा तकनीकी रूप से सक्षम ना होना।

(2) भारत द्वारा संचालित प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में देरी

(3) 'Big Brother' की छवि अन्य दक्षिण एशिया देशों मे भारत की नकारात्मक छवि बनाता है।

VISION IAS™

(4) SAARC तथा BIMSTEC जैसे संगठनों की विफलता

(5) WB तथा IMF से प्राप्त ऋणों में निहित शर्तें

वर्तमान में आवश्यकता है कि भारत अपनी ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास बढ़ाता है तथा अंतर्क्षेत्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के माध्यम से दक्षिण एशिया में ऊर्जा gap को कम कर सकता है।

Scanned with CamScanner